आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 13.09.2026 समय : 1905

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण और सम्मान के लिए लगातार कदम उठा रही है।
- जिला विधि सेवा प्राधिकरण, की ओर से द्वीप समूह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए TribeX पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों में पंजीकरण शुरू कर दिया है।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साऊथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानि क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।

प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए 'ब्रिक्स–एम.एस.एम.ई. सहयोग पोर्टल' स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया

कि शहरों के बीच बेहतर तौर–तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए 'ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब' का गठन किया गया है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए 'ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर, किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढाया है।

<><><><><><><>

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज बताया है कि देश में लगभग सतासी हजार स्वच्छता कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट – पीपीई प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही, कामकाज के सुरक्षित माहौल और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छिहत्तर हजार से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। सरकार स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण और सम्मान के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसके लिए कर्मचारियों के विवरण की रूपरेखा तैयार करने, सुरक्षा उपकरण देने, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि नौ सौ तिरासी स्वच्छता कर्मचारियों के लिए लगभग चौतीस करोड़ रुपये की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है, ताकि वे तीन सौ चौसठ वाहनों की खरीद कर सकें। यह सहायता मशीनीकृत स्वच्छता अभियानों को बढ़ावा देने के साथ–साथ कर्मचारियों के लिए आजीविका के नए अवसर भी सुनिश्चित करती है।

<><><><><><><>

जिला विधि सेवा प्राधिकरण, की ओर से श्री विजयपुरम, मायाबंदर, डिगलीपुर और कैंपबेल बे में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कैंपबेल बे में कार्यवाही वर्चुअल माध्यम से हुई। श्री विजयपुरम में बैंक रिकवरी, बीएसएनएल रिकवरी, NI Act, आपराधिक तथा मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। पोर्ट ब्लेयर में तीन, मायाबंदर में एक और डिगलीपुर में एक पीठ

गठित की गई थी। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव सम्राट राय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–अध्यक्ष शुभ्र बंद्योपाध्याय के मार्गदर्शन में किया। मायाबंदर और डिगलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी), पवित्र सेन के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

<><><><><><><>

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए TribeX पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों में पंजीकरण शुरू कर दिया है। TribeX मंत्रालय का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से भारत की जनजातीय ज्ञान परंपराओं, संस्कृति, भाषाओं, कला, वस्त्र, संग्रहालय विज्ञान और टिकाऊ आजीविका से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। UGC से मान्यता प्राप्त एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए पांच स्ट्रीम में प्रवेश दिया जा रहा है। इनमें ट्राइबल लैंग्वेज—संथाली (ओल चिकी), म्यूजियोलॉजी एवं ट्राइबल म्यूजियम मैनेजमेंट, ट्राइबल कल्चर एंड आर्ट्स, सस्टेनेबल ट्राइबल कल्चर–बेस्ड लाइवलीहुड प्रैक्टिसेज तथा ट्राइबल टेक्सटाइल्स शामिल हैं। इसके अलावा 50 से अधिक निःशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स भी सभी इच्छुक शिक्षार्थियों के लिए उपलब्ध है। पाठ्यक्रम UGC के तहत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से संबद्ध हैं। प्रत्येक पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम की फीस सात हजार पांच सौ रुपये निर्धारित की गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इन डिप्लोमा कार्यक्रमों में विशेष छात्रवृत्ति सहायता उपलब्ध है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों से इस अवसर का लाभ उठाने और TribeX के माध्यम से जनजातीय ज्ञान परंपराओं को सीखने की अपील की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण एवं विस्तृत जानकारी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक TribeX पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9933–210–933 पर संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

आकाशवाणी श्री विजयपुरम में प्रसारण सहायक के पैनल में शामिल करने के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार

का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। साथ ही, हिंदी और अंग्रेजी भाषा तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अधिकतम आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष निर्धारित की गई है। केवल श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है

<><><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। इन पदों के लिए साक्षात्कार सोलह सितम्बर को सुबह दस बजे लिया जाएगा।

<><><><><><><><>